*इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, बॉम्बे*बचन सिंह (1), बीमा कंपनी को तब तक उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता जब तक कि बीमा की पॉलिसी लेने वाले बीमित व्यक्ति के खिलाफ निर्णय प्राप्त नहीं हो जाता। इसके अलावा, दावेदारों द्वारा दावा किया गया कि विकल्प में कोई मुद्दा नहीं था, कि दुर्घटना जरनैल सिंह द्वारा लापरवाही से कार चलाने के कारण हुई थी। इस संबंध में ऐसी किसी याचिका और मुद्दे के अभाव में, दावेदारों की ओर से यह सफलतापूर्वक तर्क नहीं दिया जा सका कि वे बीमा कंपनी से किसी भी मुआवजे के हकदार थे। यह सच है कि हर अनुमान बीमा कंपनी के खिलाफ उठाया जाएगा क्योंकि वह अवसर दिए जाने के बावजूद, इस न्यायालय में पॉलिसी की एक प्रति पेश करने में विफल रही, लेकिन उक्त अनुमान बीमा कंपनी की दलीलों के अभाव में उपलब्ध नहीं है। दावेदारों ने अपनी दावा याचिकाओं में कहा कि कार का चालक जरनैल सिंह तेजी से और लापरवाही से गाड़ी चला रहा था और यह दुर्घटना कार चालक द्वारा तेजी से और लापरवाही से कार चलाने के कारण हुई थी।

9. इन परिस्थितियों में, सभी अपीलें विफल हो जाती हैं और लागत के संबंध में बिना किसी आदेश के खारिज कर दी जाती हैं।

एससीके

पहले: एमएम पुंछी, जे.

वनीत ढिल्लन,-याचिकाकर्ता।

बनाम

पंजाब विश्वविद्यालय, प्रतिवादी।

*सिविल रिट याचिका संख्या*1987 का 3735

16 दिसंबर 1987

*पंजाब यूनिवर्सिटी कैलेंडर वॉल्यूम। तृतीय*1985—अध्याय XXX (सी) पैरा 10,—प्रॉस्पेक्टस पैराग्राफ 5(बी)—याचिकाकर्ता को बी.एससी.आई (नॉन-मेडिकल) में कम्पार्टमेंट के तहत रखा गया—प्री एंट्रेंस टेस्ट के लिए आवेदन किया गया—बी.एससी. पुनर्मूल्यांकन पर संशोधित याचिकाकर्ता का परिणाम - ऐसे पुनर्मूल्यांकन का प्रभाव - याचिकाकर्ता परीक्षा के लिए पात्र - उम्मीदवारी रद्द करना - ऐसे रद्दीकरण की वैधता।

(1) 1982 पीएलआर, 280।

*आयोजित,*मुझे लगता है कि कृत्रिम स्थिति पर अड़े रहने और जो करना वांछनीय है वह न करने तथा उम्मीदवार की संभावनाओं को खतरे में डालने का शायद ही कोई वैध कारण हो। अनुच्छेद 5(बी) की भाषा, जैसा कि स्पष्ट है, प्रकृति में बहुत सटीक है, किसी भी परिस्थिति में अपवाद की अनुमति नहीं देती है। प्रॉस्पेक्टस कोई धर्मग्रंथ नहीं है और सामान्य ज्ञान उसमें दिए गए दिशानिर्देशों की व्याख्या करने और उन्हें लागू करने में प्रतिकूल नहीं है। अनुच्छेद 5(बी), जैसा कि मुझे लगता है, इस प्रभाव को छोड़कर कि यह मनमाने ढंग से सुविधाजनक है। ऐसा करने वाले विश्वविद्यालय में सामान्य ज्ञान और निष्पक्षता का अभाव है और अनुल्लंघनीयता को देखते हुए गंभीर अन्याय हो सकता है।

*(पारस*9 और 12)

माना गया कि पैराग्राफ 5 (बी) में प्रावधान है कि उम्मीदवारों की पात्रता केवल 1987 में आयोजित योग्यता परीक्षा के मूल परिणाम के आधार पर निर्धारित की जाएगी, न कि पुनर्मूल्यांकन के बाद के परिणाम पर। फिर भी पुनर्मूल्यांकन परीक्षाओं की योजना का अभिन्न अंग है। पुनर्मूल्यांकन की अवधारणा त्रुटि और संभावित सुधार को मानती है। अब, पैराग्राफ 5 (बी) के प्रयोजनों के लिए, जहां कोई त्रुटि हो या नहीं, योग्यता परीक्षा के मूल परिणाम को इस तथ्य के बावजूद अच्छा माना जाता है कि विश्वविद्यालय कैलेंडर के तहत पूर्व-विज्ञापित पुनर्मूल्यांकन परिणाम का स्थान ले लिया जाएगा। मूल परिणाम. यद्यपि विश्वविद्यालय ने अनुरोध किया है कि पुनर्मूल्यांकन का सामान्य नियम अनुच्छेद 5(बी) में सन्निहित सिद्धांतों पर लागू नहीं होगा, फिर भी सिद्धांत रूप में यह कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं दिखाता है। बल्कि इसके बेहद अवांछनीय परिणाम होंगे.

(पैरा 9 और 12)

*अनुच्छेदों के अंतर्गत याचिका*भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 में प्रार्थना की गई है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत अपने असाधारण क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए, यह माननीय न्यायालय निम्नलिखित जारी करने की कृपा करेगा: -

(i) नियम निसी;

(ii) *उत्तरदाताओं को संपूर्ण प्रासंगिक रिकॉर्ड इस माननीय न्यायालय को प्रेषित करने का निर्देश दें;*

(iii) *अनुबंध* रद्द करेंपी.7 और प्रतिवादी-पंजाब विश्वविद्यालय को निर्देश दें कि वह याचिकाकर्ता को 5 जुलाई, 1987 को आयोजित होने वाली प्री-एंट्रेंस टेस्ट में उपस्थित होने की अनुमति दे।

(iv) *कोई अन्य उचित रिट आदेश या निर्देश जारी* करेंजैसा कि माननीय न्यायालय मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में उचित समझ सकता है।

(v) *कृपया अनुलग्नक पी-1 से पी-7 की प्रमाणित प्रतियों को दाखिल करने की छूट दी जाए।'*

(vi) *रिट याचिका की एक प्रति अग्रेषण पत्र के साथ रजिस्ट्रार-प्रतिवादी के कार्यालय में लाल रूप से पहुंचा दी गई है।*

(v ii) याचिका की लागत की अनुमति दें।

*आगे प्रार्थना की गई है कि याचिकाकर्ता को 5 जुलाई को होने वाली प्री-एंट्रेंस टेस्ट में शामिल होने की अनुमति दी जाए।*1987 अपने जोखिम पर।

याचिकाकर्ता के वकील अरुण नेहरा।

प्रतिवादियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता जेएल गुप्ता, अधिवक्ता सुभाष आहूजा के साथ।

प्रलय

मदन मोहन पुंछी, जे.

1. ये दो समान रिट याचिकाएं हैं जिनमें मांगी गई राहत आम है। इनका निस्तारण सामान्य आदेश से किया जाएगा। हालाँकि, उनमें से एक यानी 1987 के सीडब्ल्यूपी नंबर 3735 को जन्म देने वाले तथ्यों को ध्यान में रखना और दूसरे यानी 1987 के सीडब्ल्यूपी नंबर 3801 को छोड़ देना सुविधाजनक होगा।

2.) पेटी याचिकाकर्ता वैनीटिल ढिल्लन ने पनियाब विश्वविद्यालय द्वारा अप्रैल, 1987 में आयोजित Ein5cB.Sc.,rtPart-IDr (मेडिकल) परीक्षा में भाग लिया। उनका परिणाम 19 मई, 1987 को घोषित किया गया था। उन्हें जारी किए गए परिणाम कार्ड में, यह दिखाया गया था कि उन्होंने भौतिकी की लिखित परीक्षा में केवल 22 अंक प्राप्त किए थे। भौतिक विज्ञान की लिखित परीक्षा के लिए आवश्यक उत्तीर्ण अंक 35 थे और इसलिए उसे भौतिकी में कंपार्टमेंट में रखा गया था। चूँकि वह मूल्यांकन से संतुष्ट नहीं थी, उसने उसी दिन यानी 19 मई, 1987 को अपने अंकों के पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन किया, इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, उसे अपने भौतिकी के पेपर के पुनर्मूल्यांकन की आवश्यकता थी। सबसे शीघ्रता से. उन्होंने 25 मई, 1987 और 5 जून, 1987 को विश्वविद्यालय को अनुस्मारक भेजे। विश्वविद्यालय ने जवाब दिया कि उत्तर-पुस्तिका के पुनर्मूल्यांकन के लिए उनका आवेदन प्रक्रियाधीन था और अंतिम परिणाम आने पर उनका परिणाम उन्हें सूचित कर दिया जाएगा। पुनर्मूल्यांकन अंततः 20 जून 1987 को नहीं किया गया, जैसा कि उनके द्वारा दावा किया गया था, बल्कि 27 जून 1987 को किया गया था, जैसा कि उत्तरदाताओं ने सुझाव दिया था।

3. पनिआब विश्वविद्यालय इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए एक प्री-एंट्रेंस टेस्ट (बाद में पीईटी के रूप में संदर्भित) आयोजित करता है।

पंजाब विश्वविद्यालय से संबद्ध कॉलेजों में। पीईटी के लिए पंजाब विश्वविद्यालय द्वारा जारी प्रॉस्पेक्टस के अनुसार, परीक्षा देने की पात्रता के लिए न्यूनतम योग्यता यह है कि उम्मीदवार को बीएससी में भौतिकी, रसायन विज्ञान, गणित और अंग्रेजी में कुल मिलाकर 50 प्रतिशत अंक प्राप्त होने चाहिए। भाग- I परीक्षा.

4. पीईटी में उपस्थित होने के लिए निर्धारित प्रपत्रों पर आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 25 जून, 1987 थी। उस तिथि तक पुनर्मूल्यांकन किया गया। याचिकाकर्ता को परिणाम के बारे में सूचित नहीं किया गया था। उसने संबंधित विश्वविद्यालय प्राधिकारियों को इन तथ्यों का खुलासा करते हुए अपना आवेदन प्रस्तुत किया। परीक्षा 5 जुलाई 1987 को होनी थी। हालाँकि, परीक्षा की तारीख से पहले, पुनर्मूल्यांकन परिणाम उपलब्ध हो गया। उसने भौतिकी में पर्याप्त उत्तीर्ण अंक प्राप्त किए थे और उसका कुल प्रतिशत 56.5 था। इन तथ्यों से यह स्पष्ट है कि यद्यपि वह आवेदन की तिथि अर्थात 25 जून, 1987 को वस्तुतः पात्र नहीं थी, लेकिन परीक्षा की तिथि अर्थात 5 जुलाई, 1987 तक पात्र थी। हालाँकि, विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने उसे उम्मीदवारी से वंचित कर दिया। पीईटी में और उसे सूचित किया कि उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी गई है क्योंकि जुलाई, 1987 की पीईटी परीक्षा के लिए प्रॉस्पेक्टस के पैराग्राफ 5 के खंड (बी) के तहत वह अयोग्य थी। प्रॉस्पेक्टस के पैराग्राफ 5 का खंड (बी) इस प्रकार है: -

> "(बी) उम्मीदवारों की पात्रता केवल 1987 में आयोजित योग्यता परीक्षा के मूल परिणाम के आधार पर निर्धारित की जाएगी, न कि पुनर्मूल्यांकन के बाद के परिणाम पर। हालाँकि, जिन उम्मीदवारों ने पुनर्मूल्यांकन के परिणामस्वरूप योग्यता परीक्षा में अंकों का आवश्यक प्रतिशत प्राप्त किया है, वे अगले वर्ष प्री-एंट्रेंस टेस्ट में उपस्थित हो सकते हैं, अन्यथा पात्र होने पर।

याचिकाकर्ता के दिमाग में शायद पंजाबी यूनिवर्सिटी कैलेंडर वॉल्यूम III 1985 का अध्याय XXX(सी) था, जिसमें पैराग्राफ 10 में प्रावधान है कि पुनर्मूल्यांकन पर प्राप्तांक मूल स्कोर का स्थान ले लेता है। पैराग्राफ 12 में प्रावधान है कि यदि पुनर्मूल्यांकन के परिणामस्वरूप कोई उम्मीदवार परीक्षा में उत्तीर्ण होता है, तो वह पुनर्मूल्यांकन परिणाम की सूचना मिलने के 10 दिनों के भीतर अगली उच्च कक्षा में प्रवेश पाने के लिए पात्र होगा। पैराग्राफ 14 में प्रावधान है कि पुनर्मूल्यांकन का परिणाम, चाहे अनुकूल हो या प्रतिकूल, पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार पर बाध्यकारी होगा। यह सोचकर कि पुनर्मूल्यांकन के परिणाम ने मूल परिणाम को पीछे छोड़ दिया है

परिणाम, उसे पीईटी में बैठने का अधिकार देते हुए, उसने इस याचिका के माध्यम से इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और अपनी याचिका के प्रस्ताव पर 29 जून, 1987 को मोशन बेंच से एक अंतरिम आदेश प्राप्त किया, इस आशय का कि उसे इसमें उपस्थित होने की अनुमति दी जाएगी। परीक्षा 5 जुलाई 1987 को उनके अपने जोखिम पर आयोजित होने वाली थी। इस न्यायालय के आदेशों के तहत, यह कहा गया है कि वह पीईटी में उपस्थित हुई थी। याचिका 23 जुलाई 1987 को स्वीकार की गई और आदेश दिया गया कि इसे संबंधित याचिका के साथ अगले दिन मेरे समक्ष सूचीबद्ध किया जाए। उस समय तक प्रतिवादियों का रिटर्न दाखिल हो चुका था, जिसे फिलहाल विज्ञापित किया जाएगा।

5.) मैंने इन याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई की और 30 जुलाई, 1987 को फैसला सुरक्षित रख लिया। इस बीच यह मेरे ध्यान में लाया गया कि दोनों याचिकाकर्ताओं ने पंजाब विश्वविद्यालय के क्षेत्र में इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए अपनी पीईटी उत्तीर्ण कर ली है। परिणामस्वरूप, आदेश पारित किया गया कि यदि प्रत्येक याचिकाकर्ता किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश पाने के लिए सफलतापूर्वक प्रतिस्पर्धा करता है, तो यह रिट याचिकाओं के परिणाम के अधीन होगा।

6.प्रतिवादी-विश्वविद्यालय अपने प्रॉस्पेक्टस के पैराग्राफ 5(बी) पर भरोसा करता है और कहता है कि यह उल्लंघन योग्य है। यह कहा गया है कि याचिकाकर्ता जो आवेदन की तिथि पर अयोग्य थी, वह अयोग्य ही रहेगी, भले ही पुनर्मूल्यांकन पर उसने परीक्षा के वास्तविक आयोजन से पहले योग्यता हासिल कर ली हो। इस तरह की याचिका का सुझाव चार्ल्स के. स्काना और अन्य बनाम डॉ. सी. मैथ्यू और अन्य (1) में सुप्रीम कोर्ट के फैसले और श्रीमती डेज़ी नरूला बनाम द में इस न्यायालय के एकल पीठ के फैसले से समर्थन प्राप्त करने के लिए दिया गया है। पंजाब सरकार और अन्य (2).

7.इन परिस्थितियों में याचिकाकर्ता की ओर से उठाई गई मुख्य दलील यह है कि प्रॉस्पेक्टस का पैराग्राफ 5 (बी) मनमाना, अनुचित और अनुचित है, क्योंकि यह मामलों की एक कृत्रिम स्थिति को बनाए रखता है और यहां तक कि लाई गई कृत्रिमता को हटाने पर भी रोक लगाता है। हालाँकि, इस उद्देश्य के लिए अकाट्य कारण मौजूद हैं।

8.विद्वान वकील ने (रविंदर पांडे बनाम पंजाब विश्वविद्यालय (3)) में मेरे द्वारा दिए गए निर्णय से ताकत हासिल करने की कोशिश की;

(1) एआईआर 1980 एससी 1230
(2) एआईआर 1984 (3) एसएलआर 690।
(3) 1985 का सीडब्ल्यूपी 3209 16 जुलाई 1985 को तय किया गया।'

जिसके तथ्य लगभग समान थे। हालाँकि, निर्णय एक समझौते पर किया गया था। पंजाब विश्वविद्यालय ने इस न्यायालय के समक्ष स्वीकार किया कि एक विशेष मामले के रूप में विश्वविद्यालय ने पीईटी में उपस्थित होने के लिए तत्कालीन याचिकाकर्ताओं की पात्रता पर आपत्ति को माफ कर दिया था और तदनुसार उन्हें 17 जुलाई, 1985 के लिए निर्धारित परीक्षा में उपस्थित होने का हकदार माना गया था। और उसके परिणाम के बारे में भी. इसके अलावा, यह माना गया कि प्री-इंजीनियरिंग परीक्षा में तत्कालीन याचिकाकर्ताओं का उत्तीर्ण प्रतिशत, एक विशेष मामले के रूप में, पुनर्मूल्यांकन द्वारा संशोधित परिणाम होगा। याचिकाकर्ता के वकील ने आग्रह किया कि याचिकाकर्ता को वही लाभ न देने का कोई आधार नहीं है, जब पिछले वर्षों के कुछ उम्मीदवारों को ऐसी रियायत दी गई थी। विश्वविद्यालय की ओर से कहा गया है कि यह एक विशेष मामला था, लेकिन चूंकि विश्वविद्यालय को हर साल ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ता है, इसलिए वह इस विषय पर न्यायिक घोषणा चाहेगा। इसलिए वापस लौटने के लिए, ध्यान केंद्रित करना होगा - कि क्या प्रॉस्पेक्टस का पैराग्राफ 5 (बी) अनुचित और मनमाना है, जिसे हटाया जा सकता है या संशोधित किया जा सकता है।

9,यह उल्लेखनीय है कि प्रॉस्पेक्टस परीक्षाओं की एक सूची प्रदान करता है, जिसमें उत्तीर्ण होने से पीईटी के लिए पात्रता निर्धारित होती है पैराग्राफ 5 (बी) में प्रावधान है कि उम्मीदवारों की पात्रता केवल 1987 में आयोजित योग्यता परीक्षा के मूल परिणाम के आधार पर निर्धारित की जाएगी और पुनर्मूल्यांकन के बाद परिणाम पर नहीं. फिर भी पुनर्मूल्यांकन परीक्षाओं की योजना का अभिन्न अंग है। पुनर्मूल्यांकन की अवधारणा त्रुटि और संभावित सुधार को मानती है। अब, पैराग्राफ 5(बी) के प्रयोजनों के लिए, चाहे कोई त्रुटि हो या नहीं, योग्यता परीक्षा के मूल परिणाम को इस तथ्य के बावजूद अच्छा माना जाता है कि विश्वविद्यालय कैलेंडर के तहत पूर्व-विज्ञापित पुनर्मूल्यांकन परिणाम का स्थान ले लिया जाएगा। मूल परिणाम. यद्यपि विश्वविद्यालय ने अनुरोध किया है कि पुनर्मूल्यांकन का सामान्य नियम अनुच्छेद 5(बी) में सन्निहित सिद्धांतों पर लागू नहीं होगा, फिर भी सिद्धांत रूप में यह कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं दिखाता है। बल्कि यह हर अवांछनीय परिणाम को जन्म देगा। यहाँ दो दृष्टांत हैं:

(i) मान लीजिए कि कोई उम्मीदवार योग्यता परीक्षा के मूल परिणाम के आधार पर पात्र है। वह अधिक अंकों या डिवीजन में सुधार की उम्मीद में पुनर्मूल्यांकन चाहता है। वह पीईटी में बैठता है और सफल घोषित हो जाता है। इसके अलावा, उसे एक इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला मिल जाता है। पुनर्मूल्यांकन परिणाम में उसे असफल घोषित किया गया। यह चलता है

बिना यह कहे कि विश्वविद्यालय स्पष्ट रूप से मेरे इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश रद्द कर देगा। क्या यह सुपरस्यूए परिणाम है जो स्थिति को नियंत्रित करेगा। यदि मैं परीक्षा को परिणामी उद्देश्यों के लिए पवित्र मानने से इनकार करता हूं तो इससे कई अवांछनीय परिणाम सामने आएंगे।

(ii) मान लीजिए कि कोई उम्मीदवार मूल परिणाम के आधार पर PUT के लिए पात्र नहीं है01 क्वॉलिफ़ाइंग परीक्षा और मान लीजिए कि क्वॉलिफ़ाइंग परीक्षा का ओंगमाई परिणाम गलत तरीके से, लापरवाही से या जानबूझकर अन्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए तैयार किया गया था। पुनर्मूल्यांकन परिणाम से उम्मीदवार को क्या मदद मिलती है, यहां तक कि आवेदन जमा करने की तारीख के बाद ही उसे पात्र घोषित किया जाता है। यह बहुत बड़े अन्याय का मामला होगा, खासकर जब त्रुटि और सुधार एक ही प्राधिकारी द्वारा किया जाना हो।

इस तरह के उदाहरणों को कई गुना बढ़ाया जा सकता है और वे दिखाते हैं कि विश्वविद्यालय मूल रूप से प्रॉस्पेक्टस में पैराग्राफ 5 (बी) प्रदान करने पर पुनर्मूल्यांकन के ठोस सिद्धांत से सहमत है और चाहता है कि गलत परिणाम उम्मीदवार पर अटक जाए, केवल इसलिए, जैसा कि सुझाव दिया गया है यह, यह समय पर पुनर्मूल्यांकन पूरा नहीं कर सकता है, अन्यथा पीईटी में देरी हो जाएगी। यह मुझे शायद ही किसी कृत्रिम स्थिति से चिपके रहने का एक वैध कारण लगता है, न कि जो किया जाना वांछनीय है और उम्मीदवार की संभावनाओं को खतरे में रखता है। अनुच्छेद 5(बी) की भाषा, जैसा कि स्पष्ट है, प्रकृति में बहुत सटीक है, किसी भी परिस्थिति में अपवाद की अनुमति नहीं देती है। लेकिन जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने चार्ल्स के. स्केरिया के मामले (सुप्रा) में कहा था, प्रॉस्पेक्टस कोई धर्मग्रंथ नहीं है और सामान्य ज्ञान उसमें दिशानिर्देशों की व्याख्या और उन्हें लागू करने के लिए हानिकारक नहीं है। पैराग्राफ 5(बी), जैसा कि मुझे लगता है, इस प्रभाव को छोड़कर कि ऐसा करना विश्वविद्यालय के लिए मनमाने ढंग से सुविधाजनक है, इसमें सामान्य ज्ञान और निष्पक्षता का अभाव है और इस असहिष्णुता को देखते हुए यह गंभीर अन्याय का कारण बन सकता है। जीवित रहने के लिए इसके पास उचित अपवाद होने चाहिए अन्यथा संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत इसकी मृत्यु हो जाएगी।

10. चार्ल्स स्कारिया के मामले (सुप्रा) में दी गई टिप्पणियों से पता चलता है कि चयन के संदर्भ में उम्मीदवारी की पात्रता आवेदन की तारीख तक हासिल करने पर जोर देती है, उसके बाद नहीं। वह

यह एक ऐसा मामला था जिसमें मेडिकल कोर्स के कुछ उम्मीदवारों को इस आधार पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त अंक दिए गए थे कि वे पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा धारक थे। सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष चयन की तिथि पर डिप्लोमा धारकों के लिए उन 10 अंकों को जोड़ने के लिए कुछ भी उचित या मनमाना सुझाव नहीं दिया गया था। वे अभ्यर्थी डिप्लोमा के लिए परीक्षा में शामिल हुए थे लेकिन उनका रिजल्ट घोषित नहीं किया गया था। परिणाम आवेदन जमा करने की तारीख के बाद घोषित किए गए, लेकिन चयन समिति द्वारा संबंधित योग्यताओं पर विचार-विमर्श करने से पहले। यह उस संदर्भ में है कि सुप्रीम कोर्ट ने निम्नलिखित बातें कहीं: -

"लेकिन इस अतिरिक्त 10 अंक अर्जित करने के लिए, डिप्लोमा

आवेदन की अंतिम तिथि को कम से कम या उससे पहले प्राप्त किया जाना चाहिए, बाद में नहीं, डिप्लोमा प्राप्त करने का प्रमाण इसे प्राप्त करने के तथ्य से अलग है। क्या उम्मीदवार ने वास्तव में डिग्री पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए आवेदन की अंतिम तिथि से पहले डिप्लोमा हासिल कर लिया है, यह प्राथमिक प्रश्न है। आवेदन के साथ डिप्लोमा का साक्ष्य प्रस्तुत करना समझदारी है, लेकिन यह गौण है। पहली तारीख को छूट

देना गैरकानूनी है, दूसरी तारीख पर ऐसा नहीं है.

और फिर दोबारा:

"कुल मिलाकर, स्नातकोत्तर डिग्री के लिए आवेदक
पाठ्यक्रम, डिप्लोमा के अतिरिक्त लाभ का अधिकार केवल तभी अर्जित करता है यदि (ए) उसने आवेदन की अंतिम तिथि को या उससे पहले डिप्लोमा परीक्षा पूरी कर ली हो, (बी) परीक्षा का परिणाम भी उस तिथि से पहले प्रकाशित हो, और (सी)) डिप्लोमा पाठ्यक्रम में उम्मीदवार की सफलता को प्रामाणिक या स्वीकार्य तरीके से चयन पूरा होने से पहले चयन समिति के ज्ञान में लाया जाता है।

इधर, याचिकाकर्ता ने आवेदन की अंतिम तिथि से पहले अपनी पात्रता की जांच पूरी कर ली है. परीक्षा का परिणाम प्रकाशित होने के बावजूद अधूरा है, क्योंकि न केवल पुनर्मूल्यांकन की अनुमति है बल्कि वास्तव में इसकी मांग भी की गई है। थर्डटीवी. ऑलिफ़िंग परीक्षा में उम्मीदवार की सफलता चयन शुरू होने से पहले अर्थात पीईटी से पहले अस्तित्व में आई न कि नवीनता को प्रतिस्थापित करती है। अत: यह स्पष्ट हो जाता है कि

उम्मीदवार ने वह सब किया है जो वह कर सकती थी। पीईटी के लिए उसका दावा उसी प्राधिकारी के समक्ष था जो पुनर्मूल्यांकन प्राधिकारी था। इस प्रकार गेंद विश्वविद्यालय के पाले में थी। इसके विपरीत, चार्ल्स के. स्केरिया के मामले में डिप्लोमा परीक्षा का परिणाम एक के हाथ में था और चयन दूसरे के हाथ में था (सुप्रा)। तथ्यों के आधार पर वह मामला पूरी तरह से अलग है। उन तथ्यों के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियाँ यथोचित परिवर्तनों सहित वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू नहीं हो सकती हैं। वहां दोनों मामले अलग-अलग प्राधिकारियों के पास थे - दोनों एक-दूसरे से स्वतंत्र थे। यहाँ यह एक ही प्राधिकारी है। विश्वविद्यालय।

11. In•s श्रीमती **itDaisyrNarula's>ecaseip(supra) sthisu** कोर्टुआस्क्वैश में चार्ल्स के. स्केरिया के भरोसे एक व्याख्याता की नियुक्तिमामला (सुप्रा) क्योंकि पद पर नियुक्ति के लिए आमंत्रित आवेदन की तिथि तक पदधारी ने नृत्य में एमए की अपेक्षित योग्यता हासिल नहीं की थी। तथ्यों के आधार पर, यह माना गया कि वह विचाराधीन पद के लिए विचार किए जाने के योग्य नहीं थी। लोक सेवा आयोग के पास जो कारण प्रचलित था कि विश्वविद्यालय ने परिणाम में देरी की, उसे इस न्यायालय ने स्वीकार नहीं किया। इसे ऐसे देखा गया मानो आयोग ने मनमाने ढंग से आवेदन की तिथि बदल दी हो; और मानो योग्यता प्राप्त करने की तिथि पर ही आवेदन किया गया हो। मेरी समझ से वह मामला भी अपने तथ्यों पर आधारित एक मामला है। तस्वीर में दो अलग-अलग प्राधिकारी थे, एक ने परिणाम घोषित करने में देरी की! v और दूसरा चयन को पकड़े हुए है। दोहराने के लिए, यह उन्हें है

यहां चरणबद्ध तरीके से बताया गया है कि मौजूदा मामले में यह एक ही प्राधिकारी है। यानी विश्वविद्यालय, जो अपने चुने हुए समय पर पीईटी आयोजित करता है और अपने चुने हुए समय पर पुनर्मूल्यांकन परिणाम फिर से घोषित करता है। दोनों शो का मास्टर होने के नाते इसे पूरे सेट में तर्कसंगतता का एक तत्व पेश करना होगा: कुछ ऐसा जो न्याय और निष्पक्षता के अनुरूप होगा। इसे दोनों दुनियाओं का सर्वश्रेष्ठ प्राप्त करने के लिए त्याग नहीं किया जा सकता, केवल इसलिए कि यह इसके लिए सुविधाजनक है। उसे स्वयं से स्वतंत्र होने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

12. गुरु इस प्रकार, उपरोक्त तर्क के लिए, चूहे**3** के रूप में**snresnutlyvi** विज्ञापन एड. टी ने प्रॉस्नेक्टस के नाराग्रान इफ़बल को जीवित रहने देना बुद्धिमानी समझा है। **-s"**निम्नलिखित योग्यताओं पर आधारित है/
■"■■उल्लेख:'

(i) विश्वविद्यालय के 5एस ने अपने पेपरों के पुनर्मूल्यांकन को यथासंभव उचित समय के भीतर निर्धारित करने का निर्देश दिया ताकि

पुनर्मूल्यांकन का परिणाम किसी भी स्थिति में पीईटी के लिए निर्धारित तिथि से पहले उपलब्ध हो सकता है।

(ii) यदि पुनर्मूल्यांकन परिणाम पीईटी के लिए निर्धारित तिथि से पहले उपलब्ध है, तो पुनर्मूल्यांकन परिणाम प्रतिस्थापित रूप से पात्रता को नियंत्रित करेगा।

, (iii) यदि पीईटी के लिए निर्धारित तिथि तक पुनर्मूल्यांकन परिणाम उपलब्ध नहीं होता है, तो उम्मीदवार को अनंतिम रूप से पीईटी में बैठने की अनुमति दी जाएगी, बशर्ते कि पुनर्मूल्यांकन परिणाम की घोषणा के बाद उसकी उम्मीदवारी को विनियमित किया जाएगा, और

(iv) उपर्युक्त योग्यताओं और अपवादों को विश्वविद्यालय कैलेंडर के साथ-साथ प्रॉस्पेक्टस में भी उपयुक्त परिवर्तन/संशोधन द्वारा सक्रिय किया जाना चाहिए, अन्यथा, प्रॉस्पेक्टस का पैराग्राफ 5 (बी) संविधान के अनुच्छेद 14 के मनमाने, अनुचित होने की शरारत के अंतर्गत आएगा। और अनुचित, भेदभाव के दोष से दूषित।

जैसा कि ऊपर कहा गया है, इस याचिका को स्वीकार किया जाना तय है और विश्वविद्यालय को पुनर्मूल्यांकन परिणाम पर याचिकाकर्ता की उम्मीदवारी को विनियमित करने का निर्देश जारी किया जाता है क्योंकि परिणाम पीईटी के आयोजन से पहले घोषित किया गया था। याचिकाकर्ताओं को अपने जोखिम पर पीईटी में उपस्थित होने की अनुमति देने वाले अंतरिम आदेश भी इस अदालत द्वारा पीईटी के लिए निर्धारित तिथि से पहले पारित किए गए थे। इस प्रकार याचिकाकर्ताओं को प्रतिस्थापित परिणाम और परिणामी लाभों का हकदार माना जाता है। याचिकाकर्ताओं को अपनी लागत चुकानी होगी।

एससीके

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

जितेश कुमार शर्मा

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

झज्जर, हरियाणा